



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429)

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 1990/श्रावण 5, 1912

No. 429]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1990/SHRAVANA 5, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पर्यावरण और बन भवालय

पर्यावरण, बन और बन्धजीव विभाग

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1990

का.आ. 595(ग्र).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते करने हुए, तटीय धेनों का संरक्षण करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि तटीय धेनों में प्रयोग और कियाकलाप पर्यावरणीय संरक्षण के सिद्धांतों और अपेक्षाओं से संगत है, प्रावश्यकता पर विचार करने के पश्चात प्रथापना करती है कि ममुद्रों, खाड़ियों, सांगर संगमों और संकरी खाड़ियों के द्वारा तटीय धारामों को जो उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक स्थल की ओर ज्वारी किया से प्रभावित है, तथा निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच की मूलि को तटीय विनियमन परियोजने के रूप में शोधित किया जाए, और उन्न तटीय विनियमन परियोजने में

उद्योगों की स्थापना, संक्रियाओं या संसाधनों आदि पर निम्नलिखित निर्भयन प्रधिरोपित किए जाएं अर्थात् :—

2. प्रतिषिद्ध कियाकलाप।

निम्नलिखित कियाकलाप तटीय विनियमन परियोजने के भीतर प्रतिषिद्ध किए जाते हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसे उद्योगों को छोड़ कर, जो तीव्रे तटीय नगर भाग से संबंधित हैं या जिन्हें तटाश मुविधाओं की आवश्यकता है उद्योगों की स्थापना;

(ii) भारत सरकार के पर्यावरण और उन संवालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 594 (ग्र), तारीख 28 जुलाई, 1989 का.आ. 966 (ग्र), तारीख 27 नवम्बर, 1989 और का.नि.आ. 1037 (ग्र), तारीख 5 दिसम्बर, 1989 की अधिसूचनाओं में विनियिष्ट रूप में परिसंकटमय पदार्थों का विनियमण या हथालना या संग्रहण या व्यय;

(iii) मत्स्य संसाधन इकाइयों जिनके अन्तर्गत मादाकरण भी है।

(iv) अपरिषटों और बहिनावों के व्यवन के लिए इकाइयों मालिकों की स्थापना;

- (v) उद्धोगों, नगरों या शहरों और अन्य मानव व्यक्तिगतानों से अमाधिन प्रपश्चित्प्राप्ति और विद्वानों का निस्सारण;
- (vi) भूमि भर्ती के प्रयोजन के लिए या अन्यथा नगर नियम प्रपश्चित्प्राप्ति का उपकरण;
- (vii) तारीय नियुत केन्द्रों से राज्य का उपकरण;
- (viii) समूद्र जल के प्राकृतिक रूप को समरूप व्यापारों के साथ बंद करना या उसमें वाधा डालना चिवाएँ उसके जो तटीय कटाव के नियन्त्रण के लिए अपेक्षित हैं;
- (ix) भूमि पुनर्वाप, बालू अट्टानों और अन्य अवतर भागों की व्यावसायिक;
- (x) मर्स्य संग्रहण या भूजल का निकालना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसका सन्तुष्टिमान या योग्यिकी;
- (xi) उत्तरवंश में विनिर्दिष्ट रूप में पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में सन्तुष्टिमान विधाकालाग;
- (xii) निम्न ज्वार ऐवा और उच्च ज्वार ऐवा के बीच कोई सन्तुष्टिमान क्रियाकलाप; और
- (xiii) बालू टिक्का, पहाड़ों, प्राकृतिक विधेयाओं की संजायट अथवा उसमें परिवर्तन करना जिसके अन्तर्गत सून्दर अनाने मनोरंजन संवर्धी और अन्य प्रयोजनों के लिए भूमुख्य परिवर्तन भी हैं।

### 3. अनुदीय क्रियाकलापों का विनियमन

अन्य सभी क्रियाकलाप, उनके सिवाय जो ऊपर पैरा 2 में प्रतिपिद्ध हैं निम्नानुमार विनियमित किए जाएँगे:—

- (1) तटीय विनियमन परिक्षेत्र के भीतर किसी क्रियाकलाप के लिए प्रानुक्त केवल तभी वी जाएगी जब निरचायक रूप से यह साधित हो जाए कि ऐसा क्रियाकलाप परिक्षेत्र की सीमा के बाहर नहीं किया जा सकता है।
- (2) निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुका अपेक्षित होगी; अर्थात्:—
  - (i) भुजाता संवर्धी व्यापारों से संबंधित सन्तुष्टिमान क्रियाकलाप जिनमें निम्न तदात्र सुविधाएँ आवश्यक हैं (उदाहरणार्थ जलावंतरण भंड, जैटी आवि);
  - (ii) ऐसे पत्तनों और वन्द्रयाहों तथा प्रकाश स्तम्भों के लिए संक्रियालय नियन्त्रित नियन्त्रित नहीं जल अप्राप्याग अपेक्षित हैं;
  - (iii) नायर त्रिवेत मंत्रित, और
- (i) पांच करोड़ लाख से अधिक विनियान वाले अन्य सभी क्रियाकलाप।
- (3) (i) तटीय गज्य और संधि राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने राज्यक्षेत्रों के भीतर ज्वाबंध 1 में दिए गए मार्गरण्क लिंगानों के अनुमार तटीय व्यापारों का पता लगाकर और उनका वर्गीकरण करके तटीय परिक्षेत्र प्रबंध व्योजना तैयार करें और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का अनुमोदन अधिप्राप्त करें तथा भूमि उपयोग आदि पर सुसंगत कानूनों और विनियमों में इन्हें सम्मिलित करें।
- (ii) ऐसी अनुमोदित व्योजनाओं की रूपरेखा के भीतर जो क्रियाकलाप ऊपर पैरा 2 और पैरा 3(2) में सम्मिलित नहीं है किए गए हैं, वे उत्तरवंश 1 में दिए गए मानवदंडों के अनुमार यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

### 4. मानीटर करने और प्रबंदन के लिए प्रक्रिया:

पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तरों पर ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो इस

प्रदोषन के निए अप्रिहोत किए जाएं, इस अधिसूचना के संशोधित उपबंद्धों को मानीटर करने और उनके प्रबंदन के लिए उनरवायी होंगे।

### 5. आक्षेप मांगना:

पर्यावरण (संशोधन) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के बंड (ब) के अधीन यह प्रधिसूचित किया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रस्तावित नियंत्रण के विशेष घोर्षा अपेक्षित फाउल करने का इच्छुक है इस अधिसूचना के गोपाल में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण, वन और वन जीव विभाग, नई दिल्ली के सचिव को लिखित में ऐसा कर सकेगा।

[ए. के. 15019/1/84-आई ए III (जिल्हा)]  
महेश प्रसाद, सचिव

### प्रत्यवर्त्य—।

जटीय देव वर्त वर्तीकरण और विकास नियमन

### नवर्तीकरण देव वर्त का वर्तीकरण

6(1) विकास गतिविधियों के विनियमन के लिए भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर के तटवर्ती भागों को ज्वार व्येणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्:—

### श्रेणी-1 (सी.आर.जे३-1):

राष्ट्रीय उदानों, अध्यारणों, आरक्षित वनों, कच्छ वनस्पति, मूरा, मण्डी और अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन धोत्र और अडे देने वाली भूमि प्राकृतिक गुरुदरता ताने पारिस्थितिक रूप से संबेदनशील और महालूपूर्ण धोत्र तथा केवल सरकार या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समग्र-प्रभव पर अधिसूचित इस प्रकार के अन्य धोत्र।

### श्रेणी-2 (सी.आर.जे३-2):

ममुद्री कियानों या उनके नजदीक नक्क पहने ही से विकिपित धोत्र इस प्रयोजन के लिए "विकिपित धोत्र" का आण्य नगरीय सीमाओं के अन्दर उम धोत्र में है जहां पहने ही काही निर्माण हो चुका है और जहां जल निकासी और पहुंच मार्ग तथा जल प्राप्ति और भूम्य मलजल निकास जैसी अन्य अधारामूल सुविधाएँ मुहूर्या कराई गई हैं।

### श्रेणी-3 (सी.आर.जे३-3):

वे धोत्र जो ओप्पाक्षेत्र यांत्र धोत्र हैं और जो श्रेणी-1 व 2 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इनमें ग्रामीण धोत्रों में तटीय धोत्र (विकिपित और प्रविकिपित) आर नगरीय सीमाओं के भीतर के धोत्र आयेंगे, जहां पर्यावरण विकास तहीं हुआ है।

### श्रेणी-4 (सी.आर.जे३-4):

सी.आर.जे३-1, सी.आर.जे३-2 और सी.आर.जे३-3 में विनिर्दिष्ट धोत्रों को छोड़कर अंद्रमान और निकोयार तथा नवदीय संगृह के तटीय भाग।

### गतिविधियों के नियमन के लिए मापदंड

6(2) तटीय भागों की विभिन्न व्येणियों में विकास या निर्माण गति विधियों को निम्ननियम भागों के अनुमार राज्य/केन्द्र शासित धोत्र स्तर पर संयंत्रित प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

### सी.आर.जे३-1

उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के आय तिनी तथा निर्माण की अनुमति नहीं हैं।

## भार जेड-२

- (1) जहां समुद्र के किनारे और विकलित किने जाने वाले प्रसारित धेव को अलग करने वाला कोई मार्ग है उप स्थिति में विद्यमान मार्ग के भूमि की ओर ही नहीं निर्माण की अनुमति दी जाए, बरतने के एक एम आई/एक ए आर के लिए विद्यमान सापेंडों महिन स्थानीय टाउन और कट्टी प्लानिंग विनियमों का पालन किया जाए ।
- (2) जहां किनारे के धेवों तथा आम गाम के विकास को असंग करने वाला कोई मार्ग नहीं है, उस स्थिति में भौजुवा संरचनाओं के समुद्र की ओर स्थानीय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विनियमों के अधीन भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- (3) विद्यमान एक एम आई/एक ए आर मापदंडों का अनुपालन करने और विद्यमान प्रयोग में परिवर्तन किए बिना प्राधिकृत भवनों के पुनः निर्माण की अनुमति दी जायेगी ।
- (4) भवनों को प्रभिलंग और फिरांग स्थानों पर आदृश और प्राचुरित इंटीरीय प्रयोग से भरो।

## सी आर जेड-३

- (1) उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक के धेव को "विकास धेव नहीं" माना जाना है और इस धेव के अन्दर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- (2) अनुबंध-२ में जलिवादित दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन किनारे के लिए आवाम होटल/समुद्री नितारों पर सैरगाह हार्नेंडे हास्म के निर्माण के लिए उच्च ज्वार रेखा के 200 और 500 मीटर के बीच के खाली चट्टानों के विकास की अनुमति है ।
- (3) उच्च ज्वार रेखा के 200 और 500 मीटर के बीच आवाम इकाईयों के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति है बरते कि यह परम्पराग्रामीकरणों और प्रयोगों की परिधि में आता हो । इस प्रकार के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति अनुबंध-२ में दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार दी जायेगी ।
- (4) उपरोक्त (1) से (3) को ज्ञान पर विद्यमान प्राधिकृत भवन के पुनः निर्माण/उसमें परिवर्तन करने की अनुमति है ।

## सी आर जेड-४

## प्रेडिग्न और निकोबार द्वीप समूह:

- (1) उच्च ज्वार रेखा के 200 मीटर के भीतर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (2) उच्च ज्वार गोमा से 200 तक 500 मीटर के बीच स्थित भवन २ नल (नितारा तल और प्रथम तल) से अधिक ऊंचाई के लही होने चाहिए, कुल आच्छादित धेव भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत में अधिक लही होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक लही होनी चाहिए ।
- (3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा उम स्थान के परिवृत्त्य से मेल खाना चाहिए ।
- (4) शटों और तटीय जल की सूंगा चट्टानों तथा बालू को निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।
- (5) सूंगा चट्टानों में तथा उनके आसपास तलभाजन तथा जल के भीतर विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा
- (6) तथापि, कुछ द्वीपगम्भीरों में तटीय भागों को भी सी आर जेड-१ प्रथमा २ प्रथमा ३ श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भागों में संवेदित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे ।

## संक्षेप समूह

- (1) भवन निर्माण की अनुमति देने सबसे द्वितीय भूमि के आकार के अनुसार उच्च ज्वार गोमा की दूरी निर्धारित करनी चाहिए । इसका निर्धारण विषेषज्ञों के परामर्श से जल-विज्ञानीय पहलुओं, भूमि कटाव तथा पारिस्थितिकीय संबद्धताओं भवित स्थानीय परिस्थितियों की तुलना में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग की प्राप्तशक्तियों को ध्यान में रखने द्वारा प्रत्येक द्वितीय के लिए किया जाना चाहिए ।
- (2) उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर के भवन २ तल (निचला तल तथा प्रथम तल) से अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए । कुल आच्छादित धेव भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत से अधिक लही होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई ९ मीटर से अधिक लही होनी चाहिए ।
- (3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा परिवृत्त्य से मेल खाना चाहिए ।
- (4) नटों तथा तटीय जल की सूंगा चट्टानों तथा बालू को निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।
- (5) नैगून तथा भूंगा चट्टानों में तथा उनके आसपास तलभाजन जल के भौतिक विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा
- (6) तथापि, कुछ द्वीपगम्भीरों में तटीय भागों को भी सी आर जेड-१ प्रथमा २ प्रथमा ३ श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भागों में संवेदित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे ।

अनुबंध-२

तटीय भागों में समुद्रक्षेत्र मैर-ग/होटल/प्रावास-गृह के लिए मार्ग-निर्देश

- (1) तटीय भागों में समुद्रक्षेत्र मैर-ग/होटल/प्रावास-गृह के निर्माण के लिए निम्नलिखित गोले होंगी ।
  - (1) परियोजना प्रसारक उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक (भूमि की ओर) तथा निम्न ज्वार और उच्च ज्वार गोमा के बीच के धेव में कोई निर्माण कार्य (अस्थायी निर्माण और कटावी तर अवश्य इस प्रकार के प्रत्ये प्रारंभिकों गहिन) नहीं करेंगे ।
  - (2) आच्छादित धेव प्लाट के प्राकार के ३३ प्रतिशत से अधिक लही होना चाहिए । युने धेव में उपयुक्त हाइवानी से राही गरीके से भू-दृश्य निर्माण किया जाना चाहिए ।
  - (3) निर्माण आस-पाम के भू-दृश्य तथा स्थानीय वास्तुकला के अनुसृत होना चाहिए ।
  - (4) भवन की कुल ऊंचाई ९ मीटर से अधिक लही होनी चाहिए और भवन दो मांजलों (भूमि तल और प्रथम तल) से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए ।
  - (5) केंद्रीय/राज्य भूमि जल बोर्ड को सहमति के बिना भूमि जल एच.टी.एल. से ५०० मीटर के अन्दर गोले नहीं लिया जाना चाहिए ।
  - (6) उच्च ज्वार रेखा के ५०० मीटर के भौतिक भवन, तरणतान तथा वेस्मेंट के बुनियादी धेव के अलावा रेत निकालने, रेतीय भागों को समस्त अन्ने या लूदाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(7) परियोजना क्षेत्र से जावित विद्युतों, ठोक अपग्रिंटों, उत्पादनों की अधिनियम और सांर स्तर भावि संकाम प्राधिकरणों, जिसमें केन्द्रीय राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड शामिल हैं तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 द्वारा निर्वाचित मात्रकों के प्रतुरूप होना चाहिए।

(8) बहिनावों और ठोक अपग्रिंटों के शोधन के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएँ। यह सुनिश्चित किया जाए कि साफ न किए गए बहिनावों और ठोक अपग्रिंटों को जल या समुद्री किनारों पर न बद्धाया जाए।

(9) लोग समुद्री किनारों तक प्रा तक, इसके लिए किन्तू दो प्लाटों के बीच कम से कम 20 मीटर छोड़ी पट्टी बहुधा कराई जाए; और,

(10) यदि परियोजना में अनेतर प्रयोजनों के लिए दत्त भूमि का उपयोग में लागा जाता हो तो इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी लेने की आवश्यकता है। परियोजना के संबंध में लागू मन्त्र केन्द्रीय और राज्य कानूनों का प्रतुपालन किया जाना चाहिए।

(2) परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में (जैसे मेरीन पाने, कच्छ बनस्पति, सूर्यों की टट्टाने, मछलियों के प्रजनन और अङ्गु देने की जगह तथा केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्र) समुद्री संराश/हाटलां/आवासों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

महेश प्रसाद, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS  
(Department of Environment, Forests and Wildlife)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 1990

S.O. 595(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after considering the need for protecting the coastal areas and for ensuring that the use and activities in the coastal areas are consistent with the principles and requirements of environmental conservation, hereby proposes to declare that the coastal stretches of seas, bays, estuaries and creeks which are influenced by tidal action (in the landward side) upto 500 metres from the High Tide Line and the land between the Low Tide Line and the High Tide Line as Coastal Regulation Zone and to impose the following restrictions on the setting up of industries, operations or processes etc. in the said Coastal Regulation Zone, namely :—

#### 2. Prohibited Activities

The following activities are declared as prohibited within the Coastal Regulation Zone, namely :—

- setting up of industries except those directly related to sea front or directly needing foreshore facilities;
- manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Notifications of the Govt. of India in the Ministry of Environment and Forests

No. S.O. 594 (E) dated 28th July, 1989, S.O. 966 (E) dated 27th November, 1989 and GSR 1037 (E) dated 5th December, 1989;

- fish processing units including warehousing;
- setting of units/mechanisms for disposal of wastes and effluents;
- discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities or towns and other human settlements;
- dumping of municipal waste for the purposes of landfilling or otherwise;
- dumping of ash from thermal power stations;
- bunding or disturbing the natural course of sea water with similar obstructions, except those required for control of coastal erosion;
- land reclamation, mining of sands, rocks and other substrate materials;
- harvesting or drawal of ground water and constructions or mechanisms thereof for such purposes;
- construction activities in ecologically sensitive areas as specified in Annexure;
- any construction activity between the Low Tide Line and High Tide Line; and
- dressing or altering of sand dunes, hills, natural features including landscape changes for beautification, recreational and other such purposes;

#### 3. Regulation of Permissible Activities

All other activities, except those prohibited in para 2 above, will be regulated as under :

- Clearance shall be given for any activity within the Coastal Regulation Zone only if it is proved conclusively that such activity cannot be located beyond the zone.
- The following activities will require clearance from the Ministry of Environment and Forests, Government of India, namely :—
  - Construction activities related to Defence requirements for which foreshore facilities are essential (e.g. slipways, jetties etc);
  - operational constructions for ports and harbours and light houses requiring water frontage;
  - thermal power plants; and
  - all other activities with investment exceeding rupees five crores.
- (i) The coastal States and Union Territory Administration shall prepare Coastal Zone Manage-

ment Plans identifying and classifying the coastal stretches within their respective territories in accordance with the guidelines given in Annexure-I and obtain approval of the Central Govt. in the Ministry of Environment and Forests and incorporate these in the relevant statutes and regulations on landuse etc.

(ii) Within the frame work of such approved plans, the activities not covered in para 2 and para 3 (2) above shall be regulated by the State Government, Union Territory Administration or the local authority as the case may be, in accordance with the norms given in annexure-I.

#### 4. Procedure for monitoring and enforcement

The Ministry of Environment and Forests and the Government of State or Union Territory and such other authorities at the State or Union Territory levels, as may be designated for this purpose, shall be responsible for monitoring and enforcement of the amended provisions of this notification.

#### 5. Inviting objections

It is notified under clause (b) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, that any person interested in filing any objection against the proposed direction, may do so in writing to the Secretary in the Department of Environment, Forests and Wildlife, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, within sixty days from the date of publication of this notification in the official gazette.

[No. K-15019|1|84-IA-III (Vol.II)]  
MAHESH PRASAD, Secy.

#### ANNEXURE I

#### COASTAL AREA CLASSIFICATION AND DEVELOPMENT REGULATIONS

##### Classification of Coastal Regulation Zone :

6(1) For regulating development activities, the coastal stretches within 500 metres of High Tide Line on the landward side are classified into four categories, namely :—

##### Category I (CRZ-I) :

Areas that are ecologically sensitive and important, such as national parks, sanctuaries, reserve forests, mangroves, corals, areas close to breeding and spawning grounds of fish and other marine life, areas of out-standing natural beauty and such other areas as are notified by the Central Government or the concerned authorities at the State|UT level from time to time.

##### Category II (CRZ-II) :

The areas that have already been developed upto or close to the shore-line. For this purpose, "developed area" is referred to as that area within the municipal limits which is already substantially built up and which has been provided with drainage and approach road and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains.

##### Category III (CRZ-III) :

Areas that are relatively undisturbed and those which do not belong to Category-I & II. These will include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped and areas within municipal limits where substantial development has not taken place.

##### Category IV (CRZ-IV) :

Coastal stretches in the Andaman & Nicobar and Lakshadweep island except those designated as CRZ-I, CRZ-II and CRZ-III.

##### Norms for Regulation of Activities :

6(2) The development or construction activities in different categories of coastal stretches shall be regulated by the concerned authorities at the State|Union Territory level, in accordance with the following norms :

##### CRZ-I

No new construction permitted within 500 metres of the High Tide Line.

##### CRZ-II

- (i) Where there is a road separating the beach and the area proposed to be developed, new constructions be permitted only on the landward side of the existing road, subject to the local Town & Country Planning Regulations including the existing norms for FSI| FAR.
- (ii) Where there is no road separating the beach area and the surrounding development, construction of building shall not be allowed on the sea-ward side of the existing structures subject to the local Town and Country Planning regulations.
- (iii) Reconstruction of the authorised buildings to be permitted subject to compliance with the existing FSI|FAR norms and without change in the existing use.
- (iv) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape.

##### CRZ-III

- (i) The area upto 200 metres from the High Tide Line is to be earmarked as 'No development zone' and no construction shall be permitted within this zone.
- (ii) Development of vacant plots between 200 and 500 metres of High Tide Line permitted for construction of lodging houses| hotel|beach resorts|holiday homes subject to the conditions as stipulated in the guidelines a: Annexure-II.
- (iii) Construction/reconstruction of dwelling units between 200 and 500 metres of the High

Tide Line permitted so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses. Building permission for such construction will be in accordance with the guidelines at Annexure II.

(iv) Reconstruction/alterations of an existing authorised building permitted subject to (i) to (iii) above.

#### CRZ-IV

##### Andaman & Nicobar Islands :

- (i) No construction of buildings shall be permitted within the 200 metres of the HTL ;
- (ii) The buildings between 200 and 500 metres from the High Tide Line should not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area should not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction should not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape;
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters should not be used for construction purposes;
- (v) Dredging and underwater blasting in and around coral formations should not be permitted; and
- (vi) However, in some of the islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III, and in such designated stretches, the appropriate regulations given for respective Categories would apply.

##### Lakshadweep Islands

- (i) For permitting construction of buildings, the distance from the High Tide Line should be decided depending on the size of the islands. This should be laid down for each island in consultation with the experts keeping in view the land use requirements for specific purposes vis-a-vis local conditions including hydrological aspects, erosion and ecological sensitivity;
- (ii) The buildings within 500 metres from the HTL should not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area should not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction should not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape;
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters, should not be used for construction purposes,

- (v) Dredging and under water blasting in and around lagoons and coral formations should not be permitted; and,
- (vi) However, in some of the Islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III. In such designated stretches, the appropriate regulations given for respective categories would apply.

#### ANNEXURE II

##### Guidelines for beach resorts/hotels/lodging houses in the coastal stretches.

7.(1) Construction of beach resorts/hotels/lodging houses in the coastal stretches will be subject to the following conditions :—

- (i) The project proponents will not undertake any construction (including temporary constructions and fencing or such other barriers) within 20 metres (in the landward side) from the High Tide Line and within the area between the low tide and high tide line;
- (ii) The covered area should not exceed 33 per cent of the plot size. The open area should be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;
- (iii) The construction should be consistent with the surrounding landscape and local architectural style;
- (iv) The overall height of construction should not exceed 9 metres and the construction should not be more than 2 floors (ground floor plus one upper floor);
- (v) Ground water should not be tapped within 500 metres of the HTL without the concurrence of the Central/State Ground water Board;
- (vi) Extraction of sand, levelling or digging of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool and basement, should not be permitted within 500 metres of the High Tide Line;
- (vii) The quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise level etc. from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central/State Pollution Control Board and under the Environment (Protection) Act, 1986;
- (viii) Necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made. It must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach;

- (ix) To allow public access to the beach, atleast a gap of 20 metres width should be provided between any two plots; and.
- (x) If the project involves diversion of forests for non-forest purpose, clearance as required under the Forest (Conservation) Act, 1980 should be obtained. The requirements of other Central and State laws

as applicable to the project should also be met with.

7.(2) In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other areas as notified by the Central/State Government), construction of beach resorts/hotels/lodging houses shall not be permitted.

MAHESH PRASAD, Secy.

